दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 13 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 283

महत्वपूर्ण एवं खास

मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं : रजनीकांत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन रजनी मक्कल मंद्रम को भंग कर दिया। इस मौके पर रजनीकांत ने कहा कि भविष्य में फिर राजनीति में आने का उनका कोई प्लान नहीं है। रजनीकांत ने 29 दिसंबर, 2020 को ऐलान किया था कि वह राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन हाल में उन्होंने कहा था कि वह राजनीति में आने के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अब उन्होंने आखिरकार सभी तरह के कयासों पर विराम लगा दिया है। रजनीकांत के फिर से राजनीति में आने की चर्चाओं के बीच तमिलनाडु की राजनीति में हलचल होने लगी थी।

अश्विनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार किया ग्रहण

नई दिल्ली (आरएनएस)। अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव आर.पी. गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। चौबे ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पर्यावरण मंत्रालय परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने यह जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले सात वर्षों में पर्यावरण मंत्रालय ने कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वन क्षेत्र को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी।

उत्तराखंड में प्रवेश हेतु कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना हुआ अनिवार्य

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने के लिए पर्यटकों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पर्यटकों पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सख्ती से जांच होगी। दूसरे राज्यों से कोरोना की रिपोर्ट के बिना आने वाले पर्यटकों को वापिस भेज दिया जाएगा। डीआईजी (लॉ एंड ऑडर) नीलेश आनंद भरणे ने पर्यटकों से अपील की है कि वह कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करें। पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटकों को उत्तराखंड प्रवेश के लिए कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भरणे ने सख्ती से कहा कि किसी भी पर्यटक को बिना सभी दस्तावेजों के उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से भले ही उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ है लेकिन सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली, यूपी समेत दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों कोरोनो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर, एंटीजन या रेपिड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर किसी भी यात्री को प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड-यूपी बॉर्डर पर पुलिस पोस्टों पर सभी की गहनता से जांच की जाएगी। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हरिद्वार में पर्यटकों की भारी संख्या से सबक लेते हुए पुलिस-प्रशासन ने भी सख्ती करने का फैसला लिया है।

अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी शीरिषा बांदला

ट्रूथ । ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के मकदस से अंतरिक्ष यात्रा पर गए 'वर्जिन गैलैक्टिक' के रिचर्ड ब्रैनसन रविवार को एक निजी स्पेसक्राफ्ट के जरिए सुरक्षित वापस आ गए हैं। अंतरिक्ष यान न्यू मैक्सिको के दक्षिणी रेगिस्तान से स्थानीय समयानुसार सुबह 8.40 बजे अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। ब्रैनसन के साथ कंपनी के पांच कर्मचारियों ने भी उड़ान भरी। ये पूरा सफर करीब 56 मिनट का रहा। ब्रैनसन ने अचानक ही पिछले दिनों ट्विटर पर अंतरिक्ष यात्रा की घोषणा की थी।

योगी की जनसंख्या नीति पर विहिप ने उठाए सवाल

» कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने विधि आयोग को लिखा पत्र

» एक बच्चे की नीति संबंधी नीति में बदलाव की मांग

» जनसंख्या असंतुलन के प्रति किया आगाह

» नीतीश बोले महज कानून से नहीं बनेगी बात

» संसद में इसी सत्र में होगी चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर संघ केअनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सवाल खड़े किए हैं। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राज्य के विधि आयोग को पत्र लिख कर एक बच्चे की नीति को खतरनाक बताते हुए इसमें बदलाव करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि इससे भविष्य में जनसंख्या असंतुलन के साथ नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ सकता है।

पत्र में कहा गया है कि नई जनसंख्या नीति में दो बच्चों वाली नीति जहां जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, वहीं दो से कम बच्चों से संबंधी नीति भविष्य में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। खासतौर से वन चाइल्ड पॉलिसी से जनसंख्या में असंतुलन के साथ भविष्य में जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ का खतरा है। ऐसे में इस नीति में एक बच्चे वाले परिवार के लिए बनाई गई नीति में तत्काल बदलाव किया जाना चाहिए।

❐ **दो बच्चे वाली नीति पर समर्थन के साथ सवाल-** पत्र में दो बच्चों की नीति का समर्थन करते हुए कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। आलोक कुमार ने अपने पत्र में विधि आयोग का ध्यान असम और केरल जैसे राज्यों की ओर खींचा है। पत्र में कहा गया है कि इन राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन है। इस कारण नई जनसंख्या नीति लागू करते समय कई अहम बदलाव किए जाने की जरूरत है।

❐ **क्या है जनसंख्या नीति-** रविवार को लाई गई जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियंत्रण केलिए कई उपाय की घोषणा की गइ है। इसमें दो बच्चों वाले परिवार को बढ़ावा देने और एक बच्चे वाले परिवार को सुविधाओं का अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की गई है। मसलन इसमें कहा गया है कि एक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। सरकारी सेवा से जुड़े ऐसे परिवारों को कर रियायत और जो सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें सरकार योजनाओं का विशेष लाभ मिलेगा। नई नीति में दो से अधिक बच्चा पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं, नौकरी से वंचित किए जाने का प्रावधान है।

❐ **नीतीश ने भी किया आगाह-** राजग की सबसे बड़ी सहयोगी जदयू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नई जनसंख्या नीति पर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि महज कानून बना कर इस समस्या का निदान संभव नहीं है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य किसी भी तरह का कानून बनाने को ले कर स्वतंत्र हैं, मगर हमारे सामने चीन का उदाहरण है। नेगेटिव ग्रोथ के बाद चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, वैसे-वैसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2040 तक देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं रहेगी।

❐ **मानसून सत्र में संसद में होगी चर्चा-** इसी महीने की 19 तारीख से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर चर्चा हो सकती है। राज्यसभा में भाजपा सांसद राकेश सिन्हा, डॉ अनिल अग्रवाल सहित कुछ सांसदों ने इस संबंध में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। लोकसभा में भी भाजपा सांसदों द्वारा बिल पेश किए जाने की संभावना है। राज्यसभा में छह अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। इस बिल में दो बच्चे वाले परिवार को बढ़ावा देने और अधिक बच्चे वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है।

यूपी एटीएस की कानपुर में बड़ी कार्रवाई

» टेरर फंडिंग में एक बड़े बिल्डर को हिरासत में लिया गया

» तीन स्लीपर सेल समेत 6 उठाए गए

कानपुर (आरएनएस)। लखनऊ में अलकायदा से जुड़े आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने कानपुर में बड़ी कार्रवाई की है। यहां एटीएस टीम ने आतंकियों के एक साथी इरशाद समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि इरशाद 15 अगस्त को होने वाले सीरियल ब्लास्ट में मिनहाज और मसीरुद्दीन की मदद कर रहा था। जबकि पेचबाग का रहने वाला लईक और एक अन्य कैरियर हैं। रिहाइशी इलाके में रहने वाले ये सभी स्लीपर सेल हैं। यूपी कमांडर शकील का इशारा मिलते ही बम और असलहे तय जगह पर पहुंचाने वाले थे।

यूपी एटीएस ने जिन 6 लोगों को उठाया है, उनमें एक बड़ा बिल्डर भी शामिल है। उस पर टेरर फंडिंग का आरोप है। बिल्डर और उसके एक पार्टनर के 13 बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। बिल्डर पूर्व में हवाला कांड से भी जुड़ा रहा है। वहीं, दो ऐसे भी लोग हिरासत में लिए गए हैं,जिन्होंने प्री.एक्टिवेटेड सिम मुहैया कराए थे। फिलहाल अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है।

कानपुर को यूपी के अतिसंवेदनशील जिलों की लिस्ट में रखा गया है। तीन साल पहले ही एटीएस पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य कमरुज्जमा उर्फ कमरुद्दीन को अरेस्ट कर चुकी है।

गडकरी ने मणिपुर में 4,148 करोड़ की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलो मीटर की लंबाई कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी देशों और पड़ोसी देशों के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और

सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। इनसे दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन सेवा की सुविधा भी मिलेगी और रोजगार और स्वरोजगार का अवसर सृजन होगा। इंफाल में परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य के लिए 5000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी और एक वर्ष के समय में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतमाला चरण द्वय के अंतर्गत राज्य में राजमार्गों के विस्तार की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और सड़क बुनियादी ढांचा मणिपुर के विकास में योगदान देगा और इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि जल, बिजली, परिवहन और संचार उद्योग के विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक बहुत ही सुंदर राज्य है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

अमित शाह ने 36 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जगन्नाथ रथयात्रा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए अमित शाह ने कहा कि वे अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में कई वर्षों से मंगला आरती में भाग लेते आ रहे हैं और हर बार यहाँ एक अलग ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज भी महाप्रभु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर सदैव अपनी कृपा व आशीष बनायें रखें। केन्द्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के नारदीपुर गांव में 25 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही स्वामीनारायण मंदिर, अडालज द्वारा नवनिर्मित शारदामणि

सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन भी किया ढ्ढ इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूँ जहाँ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई हैं कि कोई भी इंसान भूखा न सोए। इंसान ही नहीं बल्कि कोई जीव भी भूखे पेट न सोए ऐसी व्यवस्था यहां की गई है। उन्होने कहा कि हमारी संस्कृति, संस्कार और परंपराएं किसी को जानना है तो उसे नारदीपुर आना पडेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि नारदीपुर उनके लिए और भी मायने रखता है क्योंकि उनका बचपन और एसएससी तक की पढ़ाई माणसा में हुई। नारदीपुर के प्रत्येक विकास कार्य, चाहे वह दवाखाना हो, स्कूल का आधुनिकीकरण हो, बच्चों का पार्क या फिर तालाब का विकास हो, वे नारदीपुर आते रहेंगे और लोगो से मिलते रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि हमने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक आबादी वाले हर गांव का 2024 तक विकास करने की योजना बनाई है। हमारा प्रयास है कि पूरे मतक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल द्वारा शुरू की गयी किसी भी योजना के लाभ से एक भी व्यक्ति वंचित न रहें । केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय, रसोई गैस, नल द्वारा जल और बिजली न पहुंची हो। उन्होने कहा कि कोरोना के समय हमने बहुत कठिन परिस्थिति देखी। दूसरी लहर में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैला, जिससे उस पर मानवीय नियंत्रण नहीं रह सका परंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिर्फ 6-7 दिनों में ही 10 गुना ऑक्सिजन गांव-गांव और शहरों में पहुंचे ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया। हालांकि फिर भी हमने कई स्वजन गंवाएं। अमित शाह ने कहा कि अब हम ऐसा संकल्प करें कि नारदीपुर और पूरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु न हों। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की है और हम सबको टीका लगवाना चाहिये।

हिमाचल में भारी बारिश, उफान पर नदी नाले : कुल्लू में सरवरी

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर हैं। नदियों, खड्डों में जलस्तर बढ़ने से कई जगह बाढ़ का माहौल बन गया है। जिला कुल्लू में भी बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू में सरवरी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, क्योंकि नदी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। इससे सरवरी के किनारे बसी झुग्गी बस्ती को खतरा पैदा हो गया है। नदी का पानी झुग्गी बस्ती के बीच में बह रहा है ।

झुग्गी झोपड़ियों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने अपनी झुग्गियां खाली करनी शुरू कर दी हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यहां अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी करते हुए जिलावासियों से अपील की है कि नदी के तटों पर जाने से परहेज करें। आदेश न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा उन्होंने इस संदर्भ में प्रशासन और पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि नदी नालों की तरफ जाने वालों पर नजर बनाए रखें और जो आदेशों की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

संसद का मानसून सत्र 19 से : डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट में उपलब्ध होंगे वाद विवाद से जुड़े चार लाख दस्तावेज

» एक क्लिक पर मिलेगा संसद के 167 साल का इतिहास

» संसद एप के जरिए भी इसी सत्र से मिलेगी अहम जानकारियां

नई दिल्ली (आरएनएस)। जल्द ही संसद के डेढ़ सौ साल केइतिहास की जानकारी महज एक क्लिक के जरिए हासिल हो जाएगी। कुछ महीने बाद संसद की डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट में हमें साल 1854 से अब तक संसद में हुए वाद विवाद की एक-एक जानकारी मुहैया कराएगी। इस वेबसाइट में वाद विवाद से संबंधित चार लाख दस्तावेज और चालीस लाख पृष्ठ को डाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि संसद में ब्रिटिश काल से अब तक जितने भी वाद विवाद हुए हैं, उसे आम नागरिकों को सहज रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। हमारे पास 1854 से ले कर अब तक के कई दस्तावेज उपलब्ध हैं। अब तक दसवीं से 17वीं लोकसभा में हुए वाद विवाद को डिजिटल कर दिया गया है। इस साल तक 167 साल के दौरान हुए वाद विवाद को डिजिटल स्वरूप में वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएग। उद्येश्य बस इतना है कि देशवासी संसद के विभिन्न आयामों से सहज रूप से परिचित हो सकें।

एक देश एक पोर्टल- लोकसभा के पोर्टल पर देश के विभिन्न विधानसभाओं की भी

जानकारी उपलब्ध रहेगी। स्पीकर के मुताबिक देहरादून में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब स्वतंत्रता दिवस के बाद पीठासीन अधिकारियों की एक और बैठक होगी। इसमें कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा।

संसद का एप भी स्पीकर ने संसद को पूरी तरह से तकनीकी से जोडने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसी सत्र के दौरान संसद एप पेश होगा। इसमें संसद टीवी का सीधा प्रसारण, सवाल-जवाब, वाद विवाद सहित कई अन्य अहम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्पीकर ने कहा कि विशेष प्रयास के कारण अब सांसद ई नोटिस के जरिए अपने प्रश्न भेज रहे हैं। इस सत्र में कोशिश इसे सौ फीसदी तक ले जाने की है। सांसदों को पुस्तकालय के रिचर्स विभाग के जरिए ऑनलाइन किसी विषय से संबंधित डाटा चौबीस घंटे उपलब्ध है। पुस्कालय को ऑनलाइन कर दिया गया है। सांसद ऑनलाइन ही जरूरी पुस्तकें अपने घरों पर मंगा सकते हैं।

19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर 18 जून को सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। स्पीकर ने बताया कि सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। अब तक 311 सांसदों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। करीब दो दर्जन सांसदों ने स्वास्थ्य कारणों से एक भी डोज नहीं ली है। सांसदों के अतिरिक्त संसद आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। पहले की तरह सांसदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।